श्री बागड़ी : मैं चेयर का रूलिंग चाहता हूं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कोई आनरेबल मेम्बर व्यवस्था के प्रश्न पर उठे और आप से मुखातिब हो, तो क्या मंत्री महोदय को यह हक़ होता है कि वह खड़े रहें । मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I have finished one question and called another question. There cannot be a point of order in-between.

श्री बागड़ी : मैं इसको समझा नहीं हूं । मुझे समझाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके बैठ जायें ।

Co-operative Farm Societies

*154. { **Shri Yashpal Singh:** **Shri Vishwa Nath Pandey:**

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) wheher a special scheme has been formulated to help co-operative farm societies financially in Gramdan and Bhoodan areas; and

(b) how much money has been set apart for this scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) Yes Sir; A copy of the Scheme is laid on the Table of the Sabha.[*Placed in Library, See* No. LT-1482/63.] Financial assistance under the Scheme would also be available to the service cooperatives organised in the Gramdan and Bhoodan areas.

(b) A sum of Rs. one crore has been set apart for assisting cooperative societies in Gramdan and Bhoodan areas out of Rupees eight crores allotted in the Third Plan for schemes relating to settlement of landless labour.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि भूदान में जो ज़मीनें दी गई हैं वे खराब ज़मीने हैं और वे बीज का भी जवाब नहीं दे रही हैं ? तो अगर यह करोड़ रुपया किसी अच्छे काम में लगाया जाये, तो क्या उचित न होगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : भूदान में करीब करीब ४३–४४ लाख एकड़ जमीनें दी गई हैं । उनमें से ८–९ लाख एकड़ ज़मीनें बट चुकी हैं । यह सही है कि कुछ वेस्ट लैंड हैं और कुछ ज़मीनें खराब हैं, लेकिन जो ज़मीनें अच्छी हैं, उन में सर्विस कोआपरेटिव आर्गनाइज किये जाते हैं और प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए एग्रीकल्चर के लिए रुपया दिया जाता है । करीब करीब १०० फ़ार्मिंग सोसायटीज हैं उन क फार्मिंग आपरेशन्ज़ के लिए रुपया दिया जाता है । और सभी ज़मीनें खराब नहीं हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि जो ज़मीनें अभी तक अलाट नहीं हुई लैंडसूस लेबरर्ज़ में तकसीम नहीं की गई है हैं, सिर्फ़ भूदान में चली गई हैं, क्या उन पर भी यह कोबआपरेटिव लागू होगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : जहां जहां सर्विस कोपआपरेटिव या कोआपरेटिव फार्मिंग आर्गनाइज़ की जायगी—और यह आगेनाइज़शन वहां की ग्राम सभा या भूदान यज्ञ समिति पर निर्भर है—, वहां वहां मदद दी जायेगी । कितनी आर्गनाइज़ की जायेंगी, यह उन पर मुन्हसिर होगा । यह वालन्टरी मूवमेंट है । उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : ग्रामदान और भूदान के द्वारा जो ज़मीनें प्राप्त हुई हैं, उनमें कितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : करीब करीब ३०० कोआपरेटिव सोसाइटीज़ कायम की गई हैं । उनमें १०० फार्मिंग सोसाइटीज़ हैं । करीब करीब २०० या २१४–२१५ सर्विस को-आपरेटिव्ज़ हैं ।

Shri Hari Vishnu Kamath: Out of the total land gifted to Acharya Vinoba Bhave, the bhoodan leader, during the last ten years or more, what proportion of that land or how many acres of that land have been distributed among the landless, and how much of that, again, is being cultivated on a co-operative basis, and in which States particularly?

Shri S. D. Misra: I said that out of about 45 lakh acres, about 8 lakh acres have been distributed. I have no statement to indicate that this has been given all to landless labour. But the scheme is to give it to landless labour.

Shri Hari Vishnu Kamath: How much?

Shri S. D. Misra: As regards how much has been distributed, the area in the co-operative societies is 17,272 acres.

Shri Hari Vishnu Kamath: And which States?

Shri S. D. Misra: I can give the States.

The figures are as follows:—Bihar: 5,022 acres; Gujarat: 3,726 acres; Madras: 1,995 acres; Mysore; 189 acres, and UP: 6340 acres.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रिय गुप्त :

श्री प्रिय गुप्त : थैंक यू वैरी मच । मुझे बहुत खुशी है । मैं आप का आभारी हूं ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रुपया इस मद में सरकार की तरफ से दिया गया है, वह रुपया किस तरह खर्च होगा और उसका प्रापर यूटिलाइजेशन होता है या नहीं, इस को देखने के लिये सरकार ने कौन सी मैशीनरी बनाई है, उस मैशीनरी में कौन कौन संस्थायें हिस्सा ले चुकी हैं और ले रही हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र : एक करोड़ रूपया जो रखा गया है, वह को-आपरेटिव सोसाइटीज के जरिये खर्च किया जायेगा । जब वह को-आपरेटिव सोसाइटीज के जरिये खर्च होगा, उस का सुपरविज़न फिनांसिंग एजेंन्सीज़, डिस्ट्रिक्ट बैंक्स, को-आपरेटिव्ज़ के लोग खुद करेंगे । इस में से अभी खर्च कुछ ही लाख हुए हैं । जहां तक मैं समझता हूं, अभी २ फरवरी, १९६३ से यह स्कीम लागू हुई है और केवल ४–५ लाख रुपया स्टेट्स ने लिया है । आशा की जाती है कि इस साल करीब करीब २५ लाख रुपया स्टेट्स को दिया जायगा ।

श्री त्यागी : लोन है या ग्रांट ?

श्री श्यामधर मिश्र : लोन और ग्रांट दोनों —

Dr. L. M. Singhvi: The question has not been fully answered. One part of the question related to the machinery for proper utilisation of this money.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member had clubbed together three questions, and the hon. Deputy Minister has answered two.

डा० लक्ष्मीमल सिंघवी: माननीय मंत्री ने यह बताया है कि को-आपरेटिव बक्स के माध्यम से होता है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि इस का सदुपयोग होगा, इस के लिये क्या व्यवस्था की गई है ।

Mr. Deputy-Speaker: Is there any scheme for that purpose?

Shri Shyam Dhar Misra: I have said that the co-operative societies, the Bhoodan Yagna Samiti and the financing agencies will supervise the utilisation.

Shri Priya Gupta: He has not answered my question. I wanted to know what machinery was there for checking the proper utilisation of the money by the committee.

Mr. Deputy-Speaker: The co-operative societies and other organisations.

श्री प्रिय गुप्त : उस रुपये के प्रापर यूटिलाइजेशन को चैक करने के लिये कोई कमेटी बनाई गई है या नहीं, उस के बारे में कोई

जवाब नहीं दिया गया है । यह तो ठीक है कि को-आपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से खर्च होता है, मगर प्रापर यूटिलाइजेशन के लिये क्या मशीनरी है ? यह सर्वे सेवा संघ से होता है, लेकिन उस को कौन चैक करने वाला है ?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. There cannot be a discussion on that question now.

श्री विश्राम प्रसाद : अभी मंत्री जी ने बताया कि एक करोड़ रुपया को-आपरेटिव सोसाइटीज के जरिये खर्च होगा । मैं जानना चाहता हूं कि यह एक करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी चार साल के बाद इस से कोई फायदा होने वाला है या यह रुपया बिल्कुल वेस्ट चला जायेगा ।

श्री श्यामधर मिश्र : अगर फायदा न होता, तो यह स्कीम ही न बनती । फायदे के लिये ही यह स्कीम बनाई जा रही है । आशा की जाती है कि फायदा होगा । लेकिन अभी से नहीं कहा जा सकता कि कितना फायदा होगा । वह तो दो साल के बाद कहा जायेगा ।

Shri M. Malaichami: May I know whether the amount spent out of the allotted money has been spent on the organisation of societies or on the working of the societies? May I also know how many societies have been organised, State-wise and how many of them are working successfully in the States?

Shri Shyam Dhar Misra: I answered this question a little earlier. 317 societies have been organised. About 100 are being formed. About 200 are service co-operatives. The State-wise figures can also be given.

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ३० लाख एकड़ जमीन अभी तक बाकी है, क्या सरकार ने उस की व्यवस्था करने के लिये एम०पीज० की या कोई और कमेटी बनाई है । सरकार ने उस के बारे में क्या इन्तजाम किया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : उस में एम०पीज० की या और किसी कमेटी का कोई सवाल नहीं है । हर जगह भूदान यज्ञ कमेटी है और उस का एक एक्ट है । उस कमेटी की मार्फत यह जमीन बंटती है ।

Shrimati Akkmma Devi: In view of the fact that co-oerative farming societies are also located in remote and hilly areas without transport facilities, may I know whether this special scheme will also help such areas?

Shri Shyam Dhar Misra: This scheme is particularly for bhoodan areas, whether they are in hilly areas or in plains areas or in desert areas. All areas are covered. This is a scheme for bhoodan areas and gramdan villages.

श्री तुलसीदास जाधव : यह जो भूदान की जमीन है, उसके बारे में रिकाडज आफ राइट्स में क्या लिखा गया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : रिकाडज आफ राइट्स में ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है । ग्राम सभा इस की मालिक है ।

Shri D. J. Naik: What is the performance of the co-operative farming societies in gramdan and bhoodan villages?

Shri Shyam Dhar Misra: No special assessment has been made regarding farming societies in gramdan villages. The Committee set up for co-operative farming under the chairmanship of the present Chief Minister of Mysore went into this question also. They studied about 34 societies out of which one or two were gramdan village societies and they found that they are working quite all right.

Shri Ramachandra Ulaka: May I know Sir, whether Government have any proposal to merge these societies with panchayat samitis?

Shri Shyam Dhar Misra: No, there is no such proposal.

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । कोआपरेशन

के आधार पर जितने भी काम किये जा रहे हैं, वे सब के सब फेल हो चुके हैं, कोई भी सफल नहीं रहा है । उदाहरण के लिये मैं बतलाना चाहता हूं कि पानीपत की एक मिल है और वहां पर आज तक शेयरहोल्डज को एक पैसा तक नहीं मिला है । इस लिये आपने कुछ काम करना है तो व्यक्तिगत रूप से करें, सीधा किसान को अगर कुछ दे सकते तो दें । कोआपरेशन नहीं चल सकता है ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

श्री सरजू पाण्डेय : जो गांव ग्रामदान में मिल चुके हैं उन गांवों में लोगों की जमीनों पर व्यक्तिगत अधिकार क्या समाप्त हो गया है या नहीं हुआ है ? अगर समाप्त हो गया है तो वहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग शुरू करने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : जो जमीनें ग्राम दान में दी गयी हैं, उनके मालिकाना हक तो ग्राम सभाओं को चले गये हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो जोत रहे हैं । सरकार की यह पालेसी है कि कोआपरेटिव फार्मिग को जहां तक हो सके, एनकरेज किया जाये । लेकिन यह तो वहां की जो समिति है ग्रामदान की, उस पर निभर करता है । कोआपरेशन वालेंटरी है और सरकार जा कर उसको अर्गेनाइज नहीं कर सकती है ।

Shri Ram Ratan Gupta: May I know whether Government's contribution is to be given all in cash or in kind also?

Shri Shyam Dhar Misra: It will be in cash, both in the form of subsidy and also in terms of loan.

Rice Production

*156. **Shri A. K. Gopalan:**
Shri P. K. Ghosh:
Shri Kapur Singh:
Shri Kesar Lal:
Shri Yashpal Singh:
Shri D. J. Naik:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to step up rice production during the Third Plan;

(b) whether as a result of these steps, there has been any increase in the production of rice during the first two years of the Plan; and

(c) if so, to what extent?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c): A statement giving the information required is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Rice is receiving attention in the 3rd Plan in the overall programme of increasing food grains production through application of improved agricultural practices including use of fertilizers and green manures etc. The following steps have been taken to step up rice production:—

(i) Under the Intensive District Agricultural Production Programme, Raipur District in Madhya Pradesh, Shahabad District in Bihar, Tanjore District in adras and West Godavri District in Andhra Pradesh have been selected for intensive rice cultivation.

(ii) Forty important rice growing districts possessing high potentiality for increasing rice producition have also been selected and a package of improved practices is proposed to be taken in them with effect from Kharif season of 1963.

(iii) Japanese method of paddy cultivation is being popularised. An area of 8.84 million acres is reported to have been covered with this programme in the year 1961-62.

(iv) Four demonstration centres have been opened in collaboration with the Government of Japan where Japa-